प्रेस विज्ञप्ति

05.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने फेमा, 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स आरआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर 16.19 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है।

ईडी ने आरआर ग्रुप कंपनियों में इस कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आरआर इंडस्ट्रीज पीटीई लिमिटेड के मामले में जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि मेसर्स हनुदेव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे एचआईपीएल के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा सिंगापुर में पंजीकृत कंपनी मेसर्स आरआर इंडस्ट्रीज सिंगापुर पीटीई लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 16.19 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण किया गया था, और आरबीआई दिशानिर्देशों और फेमा विनियमों का पालन नहीं किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स हनुदेव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल) ने आरआर इंडस्ट्रीज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (आरआरआईएसपीएल) नामक एक कंपनी की स्थापना की और इंडोनेशिया और आसपास के क्षेत्रों में खनिज व्यापार, विशेष रूप से कोयला, में शामिल होने के बहाने 16.19 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि, जांच से पता चला कि इस निवेश के माध्यम से कोई वास्तविक संपत्ति नहीं बनाई गई थी, और एचआईपीएल या इसकी समूह कंपनियों द्वारा भारत में धन वापस लाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए थे। यह निवेश इंडोनेशियाई कंपनी नोवेम कोल रिसोर्सेज (एनसीआर) में किया गया था, जिसका प्रबंधन एचआईपीएल के आर. रवि के चचेरे भाई रामनाथ द्वारा किया जाता है। इस पारिवारिक संबंध के बावजूद, रवि एनसीआर से परिचालन या रिटर्न के बारे में कोई विश्वसनीय दस्तावेज या स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। पिछले 14 वर्षों में, एनसीआर से कोई रिटर्न या संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, और रवि या एचआईपीएल द्वारा निवेशित धन को वापस पाने या सहमत ब्याज-मुक्त अवधि की समाप्ति के बाद देय ब्याज का दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस निवेश को अंततः बिना किसी ठोस औचित्य के एचआईपीएल की पुस्तकों में लिख दिया गया, और रवि का यह स्पष्टीकरण कि खदान के स्वामित्व पर अनिश्चितता के कारण यह सलाह के आधार पर किया गया था, को भी अविश्वसनीय माना गया। इन कार्रवाइयों से पता चलता है कि रवि, एचआईपीएल और उनके सहयोगियों ने नियामक जांच से बचते हुए निजी लाभ के लिए विदेशों में धन जमा करने का जानबूझकर प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, मेसर्स बिल्ड इंडिया कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी के बयान इस दावे का समर्थन करते हैं कि यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित एक विदेशी इकाई को धन हस्तांतरित करने का स्पष्ट मामला था।